

प्रेषक,

सुभाष कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या-477/XXV(1)/2011

वित्त अनुभाग-1

देहरादून दिनांक 11 मार्च, 2011

विषय:- कार्य नियमावली, 1975 के नियम-4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या- 54/XXVII(1)/2005 दिनांक 15 जनवरी, 2005 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें कार्य नियमावली, 1975 (Rules of Business) के नियम-4(2) के उप नियम क, ख, ग, तथा घ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया था। नियम 4 (2) की व्यवस्था निम्नवत् है:-

4(2)- जब तक कि मामला वित्त विभाग से दिये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृत करने या निधियों का विनियोग या पुनर्विनियोग करने की शक्ति से पूर्णतया समाप्त न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति बिना कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा-

- (क) जिससे राजस्व का परित्याग सन्निहित हो या कोई ऐसा व्यय सन्निहित हो जिसके लिये विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो,
- (ख) जिससे भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का अभ्यर्पण या खनिज या वनज या जलशक्ति अधिकार का अनुमोदन, अनुदान पट्टा या अनुज्ञप्ति या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई सुझाव या विशेषाधिकारी सन्निहित हो,
- (ग) जो पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की सदस्य संख्या, या सरकारी सेवकों के वेतन या भत्ते या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित हो,
- (घ) जो अन्यथा वित्त से सम्बन्धित हो, चाहे उसमें व्यय सन्निहित हो या नहीं,

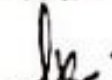
स्पष्टतः वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण भी जिनमें व्यय सन्निहित न हो परन्तु अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी नहीं किया जायेगा।

कार्य नियमावली की उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद प्रायः यह देखा जा रहा है कि प्रशासनिक विभागों द्वारा पदों के सृजन, वेतनमान संशोधन/उच्चीकरण तथा राज्य आकस्मिकता निधि से धनराशि के अग्रिम आहरण तथा अन्य प्रकरणों जिनमें वित्तीय उपाशय निहित होता है पर वित्त विभाग के परामर्श एवं पूर्व सहमति के बिना माननीय मुख्यमंत्री जी का सीधे अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाता है। इससे जहाँ एक ओर कार्य नियमावली में उल्लिखित व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है वहीं दूसरी ओर वित्तीय अनुशासन लागू करने में कठिनाई होती है। उच्च स्तर से अनुमोदन के बाद यदि प्रस्ताव के औचित्य पर वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया/नियम के परिदृश्य में सहमति दिया जाना सम्भव नहीं होता तब वित्त विभाग के समक्ष असमजसंपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

अतः कार्य नियमावली के नियम 4(2) की व्यवस्थाओं के अनुरूप वित्तीय उपाशय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण जो अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त करने के पूर्व वित्त विभाग का परामर्श अनिवार्य रूप से पहले प्राप्त किया जाये।

भविष्य में उक्त निदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निदेशों का अनुपालन न किये जाने की स्थिति को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी की वरिष्ठ पंक्ति में तदनुसार इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

भवदीय

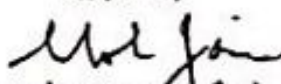

(सुमेश कुमार)
मुख्य सचिव।

संख्या:- 477 /xxvii(1)/2011 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओवरसैय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।

आज्ञा से,


(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

वित्त अनुभाग-7

देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2019

विषय:- कार्य नियमावली, 1975 के नियम-4(2) का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-54/xxvii(1)/2005 दिनांक 15 जनवरी, 2005 एवं शासनादेश संख्या-477/xxvii(1)/2011 दिनांक 11 अगस्त, 2011 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें कार्य नियमावली, 1975 (Rules of Business) के नियम-4(2) के उप नियम क, ख, ग तथा घ में उल्लिखित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही करने हेतु निदेशित किया गया था। कार्य नियमावली में नियम-4(2) की व्यवस्था निम्नवत् है:-

4(2)-जब तक कि मामला वित्त विभाग से दिये गये किसी सामान्य या विशेष आदेश द्वारा प्रदत्त व्यय स्वीकृत करने या विनियोग या पुनर्विनियोग करने की शक्ति से पूर्णतया समावृत्त न हो, तब तक कोई भी विभाग वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई ऐसा आदेश जारी नहीं करेगा-

- (क) जिससे राजस्व का परिचय सन्निहित हो या कोई ऐसा व्यय सन्निहित हो जिसके लिये विनियोग अधिनियम में कोई उपबन्ध न किया गया हो,
- (ख) जिससे भूमि का कोई अनुदान या राजस्व का अन्वर्पण या खनिज या वनज या जलशक्ति अधिकार का अनुमोदन, अनुदान पट्टा या अनुज्ञप्ति या ऐसे अनुमोदन के सम्बन्ध में कोई सुझाव या विशेषधिकारी सन्निहित हो,
- (ग) जो पदों की संख्या या श्रेणी, या किसी सेवा की सदस्य संख्या, या सरकारी सेवकों के वेतन या गतों या उनकी सेवा की किन्हीं अन्य शर्तों से सम्बन्धित हो, जिसमें वित्तीय मामला निहित हो,
- (घ) जो अन्यथा वित्त से सम्बन्धित हो, चाहे उसमें व्यय सन्निहित हो या नहीं,

स्पष्टतः वित्तीय उपाय के समस्त प्रकरण तथा वे प्रकरण भी जिनमें व्यय सन्निहित न हो परन्तु अन्यथा वित्त विभाग से सम्बन्धित हो पर वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना कोई आदेश प्रशासकीय विभाग द्वारा जारी नहीं किया जायेगा।

2- कार्य नियमावली की उक्त स्पष्ट व्यवस्था के बावजूद कतिपय विभागों द्वारा वित्तीय उपाशय से सम्बन्धित प्रकरणों पर वित्त विभाग की सहमति के बिना स्वयं निर्णय लिया जा रहा है। यह स्थिति वित्तीय अनुशासन के दृष्टि से उचित नहीं है।

अतः इस सम्बन्ध में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्य नियमावली, 1975 के प्रावधानानुसार वित्तीय उपाशय से सम्बन्धित मामलों में निर्णय, वित्त विभाग की सहमति के पश्चात् लिया जायेगा। इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निर्देशों का अनुपालन न करने पर वित्तीय अनियमितता को गंभीरता से लिया जायेगा तथा सम्बन्धित अधिकारी की बरिस्त्र पंजिका में तदनुसार इसका उल्लेख कर दिया जायेगा।

भवदीय,

(छत्पल कुमार सिंह)

मुख्य सचिव।

संख्या- /xxvii(7)40(9)2010-11/2019 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराँय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
3. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
4. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी/विभागीय लेखा/आडिट विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि कृपया वित्तीय मामलों से सम्बन्धित उक्त आदेशों/निर्देशों से इतर जारी आदेशों, जिनमें वित्त विभाग की सहमति अंकित न हो, का संज्ञान न लिया जाय। तदनुसार कृपया अपने अधिनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
5. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
6. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(अमित सिंह नेगी)

सचिव।